मेजर ज्ञान सिंह *बनाम* श्री एस पी बत्रा (*शर्मा, न्यायमूर्ति*)

सिविल अपील

एस. एस. संधावालिया और एम. *आर. शर्मा, न्यायमूर्ति के समक्ष*

मेजर ज्ञान सिंह— अपीलकर्ता

बनाम

श्री एस पी बत्रा, —*प्रतिवादी*

नियमित प्रथम अपील 1970 *की सं. 46*

26 मई, 1972

टॉर्ट्स का कानून—दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए क्षतिपूर्ति—के लिए सूट—प्रतिवादी ने वादी पर मुकदमा चलाने के लिए पुलिस की मशीनरी को गति दी, जिसके परिणामस्वरूप उसे बरी कर दिया गया—क्या एक अभियोजक नहीं है और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है—किसी व्यक्ति को बरी करना—क्या आवश्यक रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि अभियोजन उचित या संभावित कारण के बिना था—सिविल कार्रवाई का गठन करने वाली आपराधिक शिकायत के तथ्य- क्या अभियोजक की ओर से दुर्भावना का अनुमान लगाया जाता है।

अभिनिर्धारित किया कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए नुकसान के मुकदमे में एक प्रतिवादी केवल तभी दायित्व से बच सकता है जब वह पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने सच्ची और सही जानकारी रखता है, जिसके पास वादी के खिलाफ लगाए गए अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार है। जहां एक प्रतिवादी भौतिक तथ्यों को छुपाता है या उन्हें अनुचित सीमा तक विकृत करता है, उसे यह आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह अभियोजक नहीं था। यदि नुकसान के लिए उसके दायित्व की अन्य शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो वह अपनी कार्रवाई के परिणामों से बच नहीं सकता क्योंकि मजिस्ट्रेट या पुलिस की एजेंसी ने भी हस्तक्षेप किया था। (पैरा 13 and 14)

अभिनिर्धारित किया कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के मुकदमे में, यह साबित करने का बोझ कि कार्यवाही बिना किसी उचित और संभावित कारण के शुरू की गई थी, वादी पर है जो नुकसान की मांग करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले की कार्यवाही में वादी को बरी करना कभी-कभी एक धारणा को जन्म दे सकता है, कि उसके अभियोजन के लिए कोई उचित और संभावित कारण नहीं था, लेकिन यह धारणा खंडन योग्य है। इस तरह के मुकदमे में प्रतिवादी को केवल यह साबित करना है कि तथ्य और परिस्थितियां मौजूद थीं जिसने उसके मन में एक विश्वास को जन्म दिया कि दूसरा पक्ष दोषी था। इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखने या तौलने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि कानून की अदालत द्वारा किया जाएगा, अन्यथा उन सभी मामलों में जिनमें अभियोजन विफल हो जाता है, शिकायतकर्ता या अभियोजक नुकसान के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। उचित और संभावित कारण की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर विचार करते समय एक न्यायालय को परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करना होगा। केवल इसलिए कि अभियोजक ने यहां और वहां जानबूझकर झूठ पेश किया था, यह साबित करने के लिए नहीं लिया जा सकता है कि संभावित कारण पूरी तरह से अनुपस्थित था। न्यायालय को मामले के मूल तक पहुंचना होगा और यह देखना होगा कि अपराध का उप-स्तर मौजूद है या नहीं। इसके अलावा, उचित और संभावित कारण के अस्तित्व को उस समय उसकी मनःस्थिति के संबंध में आंका जाना चाहिए जब प्रतिवादी ने कार्यवाही शुरू की थी।

(पैरा 15)

अभिनिर्धारित किया कि अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि आपराधिक शिकायत में तथ्य सिविल कार्रवाई का भी गठन करते हैं, फिर भी यदि अभियोजक के पास आपराधिक कानून को गति देने के लिए एक उचित और संभावित कारण है, तो केवल यह तथ्य कि 'उसने एक नागरिक उपचार का पीछा किया होगा, उसे दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं बना सकता है। उचित और संभावित

कारण की अनुपस्थिति कभी-कभी अदालत को दुर्भावना का निष्कर्ष निकालने का अधिकार दे सकती है, लेकिन जब अभियोजन पक्ष को उचित विश्वास पर आधारित पाया जाता है, तो अभियोजक के खिलाफ दुर्भावना का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

(पैरा 17 and 21)

श्री आरएस गुप्ता, वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, चंडीगढ़ की अदालत के दिनांक 11 नवम्बर, 1969 के आदेश से नियमित प्रथम अपील, जिसमें *वादी के वाद को खारिज कर दिया गया और पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया।*

जे. वी. गुप्ता और जी. सी. गर्ग, अधिवक्ता, *अपीलकर्ता के लिए.*

एच. एल. सरीन, अधिवक्ता, एम. एल. सरीन अधिवक्ता, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता:

निर्णय

शर्मा, न्यायमूर्ति—यह पहली अपील 11 नवंबर, 1969 को वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा दिए गए फैसले और डिक्री से उत्पन्न होती है। विवाद को जन्म देने वाले तथ्यों को संक्षेप में निम्नानुसार कहा जा सकता है: -

(2) प्रतिवादी के पास चंडीगढ़ के सेक्टर 9-ए में एक प्लॉट नंबर 57-डी था, जिसे वह बेचना चाहता था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने दोस्त आर एन चोना को एक पत्र लिखा था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि वह उपर्युक्त साजिश को निपटाने का इरादा रखते थे। श्री आर. एन. चोना ने चंडीगढ़ में मैसर्स पी. एल. साहनी एंड कंपनी, प्रॉपर्टी डीलर्स से संपर्क किया और उनके साथ इस मामले पर चर्चा की। चर्चा के दौरान, प्लॉट की कीमत 7,500 रुपये तय की गई और उक्त प्रॉपर्टी डीलरों ने इस प्लॉट के बिक्री मूल्य के खिलाफ अग्रिम के रूप में 500 रुपये का क्रॉस चेक श्री चोना को प्रतिवादी को अग्रेषित करने के लिए सौंप दिया। श्री चोना ने 4 मार्च, 1960 के अपने पत्र के साथ प्रतिवादी को यह चेक भेजा। श्री चोना और प्रतिवादी के बीच कुछ और पत्रों का भी आदान-प्रदान किया गया। प्रतिवादी ने 16 मार्च, 1960 को प्रॉपर्टी डीलर्स के मेसर्स पीएल साहनी एंड कंपनी को लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने प्लॉट की कीमत के रूप में 6,862.25 रुपये की राशि का भुगतान किया था, कि डीलर कमीशन केवल 2 प्रतिशत होगा, कि प्लॉट के पंजीकरण और हस्तांतरण में शामिल लागत का भुगतान खरीदार द्वारा किया जाएगा। और वह -

> उन्होंने कहा, 'लेनदेन के लिए चंडीगढ़ आने में लगने वाले समय और धन को देखते हुए यह बहुत सराहनीय होगा कि मेरी ओर से प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा हस्तांतरण पूरा किया जा सकता है। उनसे अनुरोध किया जा सकता है कि वे मुझे भरने के लिए एक प्रोफार्मा भेजें, और यदि आवश्यक हो तो मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि ये नियम और शर्तें डीलरों को स्वीकार्य थीं, तो प्रतिवादी को 7,500 रुपये की उद्धृत कीमत पर प्लॉट जारी करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मैसर्स पी. एल. शनि एंड कंपनी, प्रॉपर्टी डीलर्स ने प्रतिवादी द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए, 19 मार्च, 1960 के अपने पत्र में निम्नानुसार उल्लेख किया: –

> "(ग) चूंकि उपर्युक्त साइट अभी तक सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है, इसलिए इसे दोनों पक्षों द्वारा 2 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित हलफनामों पर क्रेता पक्ष को हस्तांतरित किया जा सकता है और हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए विक्रेता पक्ष

की उपस्थिति बिल्कुल आवश्यक नहीं है। हम जल्द ही हस्तांतरणकर्ता यानी श्री एसपी बत्रा का हलफनामा आपके हस्ताक्षर, सत्यापन और वापसी के लिए आपके पास भेजेंगे, ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

(3) इस स्तर पर, अपीलकर्ता, जो भारतीय सेना में एक मेजर के रूप में सेवानिवृत्त हुए, ने चंडीगढ़ में एक भूखंड प्राप्त करने के लिए उक्त प्रॉपर्टी डीलरों से संपर्क किया। मेसर्स पीएल साहनी एंड कंपनी ने सुझाव दिया कि वह प्रतिवादी से संबंधित भूखंड 7,500 रुपये की राशि में खरीद सकते हैं। अपीलकर्ता ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 21 मार्च, 1960 को उक्त प्रॉपर्टी डीलरों को अग्रिम के रूप में 750 रुपये की राशि का भुगतान किया। उसी दिन, उक्त प्रॉपर्टी डीलरों ने हस्तांतरण के मसौदा हलफनामे की दो प्रतियां भेजीं जिन्हें प्रतिवादी द्वारा पूरा किया जाना था और प्लॉट के हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिए प्रॉपर्टी डीलरों को वापस करने के लिए कहा गया था। प्रॉपर्टी डीलरों के इस पत्र का प्रतिवादी द्वारा जवाब नहीं दिया गया और 2 मई, 1960 को प्रॉपर्टी डीलरों ने प्रतिवादी द्वारा पूरा और शपथ लेने के लिए मसौदा हलफनामों का एक नया सेट भेजा। 15 मई, 1960 को, प्रतिवादी ने प्रॉपर्टी डीलरों को लिखा कि वह कुछ दिनों में पूरा मसौदा हलफनामा भेज देगा। 20 मई, 1960 को, अपीलकर्ता ने उक्त प्रॉपर्टी डीलरों को शेष मूल्य के रूप में 6,750 रुपये और डीलर कमीशन के रूप में 150 रुपये की राशि का भुगतान किया। इस समय तक, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी को प्लॉट के लिए कुछ अधिक कीमत की पेशकश की जा रही थी और उसकी पत्नी ने 27 मई, 1960 के अपने पत्र के माध्यम से प्रॉपर्टी डीलरों को लिखा कि उन्हें न्यूनतम मूल्य के रूप में 8,000 रुपये में प्लॉट खरीदने के लिए किसी पार्टी से संपर्क करना चाहिए। इस पर, प्रॉपर्टी डीलरों ने विरोध का एक पत्र भेजा और जोर देकर कहा कि प्रतिवादी को पहले से तय किए गए 7,500 रुपये के लिए प्लॉट बेचना चाहिए। प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा प्रतिवादी को भेजे गए 1 जुलाई, 1960 के पंजीकृत पावती देय पत्र, प्रदर्शनी पी. डब्ल्यू. 4/6 का सामग्री भाग निम्नानुसार है: –

"आपके आश्वासन पर, खरीदार पक्ष द्वारा खरीद मूल्य की कुल राशि का भुगतान किया गया है।

इस समय तक, अपीलकर्ता कुछ बेचैन हो गया। उन्होंने चंडीगढ़ के संपदा अधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि प्रतिवादी को किसी और को भूखंड बेचने से रोका जाए। 3 अगस्त, 1960 को प्रतिवादी ने प्रॉपर्टी डीलरों को वापस लिखा और इस पत्र में, अन्य *बातों के साथ-साथ,* निम्नानुसार उल्लेख किया गया था : –

पत्र में कहा गया है, 'आपकी ओर से कोई पत्राचार नहीं मिलने की पृष्ठभूमि के साथ, आपके पत्र असभ्य और आपकी स्थिति की व्यावसायिक चिंता के अनुरूप प्रतीत होते हैं। मामले को अंतिम रूप देने में मेरी ओर से कोई अनिच्छा नहीं है, जबकि सौदा पूरा नहीं हुआ था, किसी अन्य पक्ष ने स्वतंत्र रूप से मुझे भूखंड के लिए बेहतर कीमत की पेशकश की थी और चूंकि आप सौदे को संभाल रहे थे, इसलिए मामले को आगे विचार के लिए भेजा गया था। आपकी राय में, जैसा कि 18 जुलाई के आपके पत्र में कहा गया है, अग्रिम राशि स्वीकार करने के बाद यह मेरे लिए कानूनी और नैतिक रूप से सही नहीं था। आज भी मेरे द्वारा चेक भुनाया नहीं गया है और इस प्रकार, इस संबंध में मुझ पर कोई देयता नहीं बनती है। चेक का नकदीकरण आपके बैंक खाते के रिटर्न से स्पष्ट होगा। जैसा कि मेजर ज्ञान सिंह ने कहा था, आपके द्वारा संलग्न उनके पत्र की एक प्रति, कि उन्होंने आपके पास भूखंड की पूरी कीमत जमा की थी, मुझे विधिवत सूचित नहीं किया गया था।

(4) प्रॉपर्टी डीलरों ने प्रतिवादी के इस पत्र का जवाब 9 अगस्त, 1960 को अपने पत्र के *माध्यम से* दिया , जिसमें उन्होंने यह नोट करने के लिए खेद व्यक्त किया कि उनके पत्र समय पर प्रतिवादी तक नहीं पहुंच रहे थे। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि 2 मई, 1960 के एक पंजीकृत पावती देय पत्र के तहत उन्हें भेजे गए हलफनामों को पूरा करें और उन्हें जल्द से जल्द भेजें। प्रॉपर्टी डीलरों के 9 अगस्त, 1960 के पत्र के जवाब में, प्रतिवादी ने उन्हें 17 अगस्त को लिखा था। 1960 में, वह अपने बैंकरों को संग्रह के लिए बयाना राशि का चेक भेज रहे थे और यह कि डीलरों के कमीशन से कम आय की शेष राशि उन्हें जल्द से जल्द अग्रेषित की जा सकती है। उन्होंने प्लॉट के हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रॉपर्टी डीलरों को विधिवत सत्यापित हलफनामा भी भेजा। 27 अगस्त, 1960 को चंडीगढ़ के संपदा अधिकारी को एक आवेदन दिया गया था, जिसमें प्रतिवादी से संबंधित भूखंड को अपीलकर्ता के पक्ष में स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था। इस आवेदन पर प्रतिवादी की ओर से श्री आहूजा के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें प्रॉपर्टी डीलरों का कर्मचारी बताया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसे नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित करना आवश्यक है: –

"महोदय, यह निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है: –

(1) मैंने प्लॉट नंबर 1 में अपने अधिकार और शीर्षक स्थानांतरित कर दिए हैं। सेक्टर-9-ए (आरपी नंबर 168) मेजर ज्ञान सिंह सी/ओ एफ/3, सेक्टर 8-सी, चंडीगढ़ के पक्ष में विचार के साथ।

(2) कि मुझे ऊपर नामित हस्तांतरणी से पूरा पैसा मिला है।
(3) कि इस लेन-देन में कोई मुनाफाखोरी शामिल नहीं है।
(4) कि मैंने पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के अधीन हस्तांतरणकर्ता के पक्ष में अपने अधिकारों और उपाधियों को स्थानांतरित कर दिया है।

इन परिस्थितियों में यह अनुरोध किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित भूखंड को ऊपर नामित हस्तांतरणकर्ता के पक्ष में स्थानांतरित किया जाए और उपकृत किया जाए।

स्थानांतरणकर्ता का शपथ पत्र संलग्न है। आपकी ईमानदारी से,

(एसडी).....
दुर्वाच्य
एस. पी. बत्रा के लिए,
सामान्य अधीक्षक,
डी. वी. सी. दुर्गापुर,
थर्मल पावर स्टेशन,
पी.ओ. दुर्गापुर, इस्पात परियोजना, जिला बर्दवान (पश्चिम बंगाल)।

इस आवेदन के साथ, प्रतिवादी द्वारा भेजा गया हलफनामा और अपीलकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन भी संपदा अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था। यह हलफनामा और आवेदन निम्नानुसार हैं: –

"स्थानांतरण का हलफनामा।

मैं, एस. पी. बत्रा, रेजिडेंट इंजीनियर, डीवीसी दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस दुर्गापुर स्टील प्रोजेक्ट, जिला बर्दवान (पश्चिम बंगाल) सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं कि मैं साइट नंबर 57, सेक्टर 9-ए (आरपी नंबर 168), चंडीगढ़ कैपिटल में अपना शीर्षक गांव और डाकघर दाखा के श्री काहन सिंह के बेटे मेजर ज्ञान सिंह को हस्तांतरित करना चाहता हूं। जिला लुधियाना, और इसके हस्तांतरण के बाद साइट पर कोई दावा नहीं होगा। इस लेन-देन में कोई मुनाफाखोरी शामिल नहीं है। मैंने सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी योजना के तहत कोई ऋण नहीं लिया है।

दिनांक 16 अगस्त, 1960।

(एसडी) . . . .

एस. पी. बत्रा,
(एस. पी. बत्रा),
डेपोनेंट।

अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन निम्नानुसार है: –

"

संपदा अधिकारी, राजधानी परियोजना, चंडीगढ़।

सर

प्लॉट नंबर 57, सेक्टर 9-ए, आरपी नंबर 168 के हस्तांतरण के लिए आवेदन।

यह निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:-

कि मैंने उपरोक्त उल्लिखित भूखंड के अधिकार और शीर्षक श्री एस पी बत्रा से विचार के साथ खरीदे हैं।

कि मैंने ऊपर नामित हस्तांतरणकर्ता को पूरी राशि का भुगतान किया है।

कि इस लेन-देन में कोई मुनाफाखोरी शामिल नहीं है।

ऊपर बताई गई परिस्थितियों के तहत, ऊपर उल्लिखित भूखंड को मेरे पक्ष में स्थानांतरित किया जा सकता है और बाध्य किया जा सकता है।

आपकी ईमानदारी से,

(एसडी) मेजर ज्ञान सिंह,

जेड कोमोन जोन सिग्नल कंपनी
सी/ओ 56 ए.पी.ओ., नई दिल्ली।
वर्तमान पता: एफ/3, सेक्टर 8-सी, चंडीगढ़।

(5) संपदा कार्यालय में प्राप्त प्रक्रिया के अनुसार, प्लॉट का हस्तांतरण अपीलकर्ता के पक्ष में किया गया था और प्रतिवादी को तदनुसार सूचित किया गया था। यह प्रतिवादी द्वारा प्रॉपर्टी डीलरों को संबोधित 9 नवंबर, 1960 के पत्र से स्पष्ट है, जो निम्नानुसार है: –

"विषय/-प्लॉट नंबर 57, सेक्टर 9-ए, चंडीगढ़ की बिक्री

प्रिय महोदयगण

कृपया मेरे पत्र संख्या 12का संदर्भ लें। (ख) दिनांक 17 अगस्त, 1960 का एक पूर्ण शपथ-पत्र जिसमें मेरी उपरोक्त सम्पत्ति की बिक्री के संबंध में एक पूर्ण शपथ पत्र आपकी आवश्यक कार्रवाई के लिए आपके पास भेजा गया था।

मुझे एस्टेट ऑफिसर, कैपिटल प्रोजेक्ट, चंडीगढ़ से सलाह मिली है कि उन्होंने मेजर ज्ञान सिंह, एफ/3, सेक्टर > 8-सी, चंडीगढ़ को उपरोक्त भूखंड पर अधिकार हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, मुझे लगता है कि बिक्री के संबंध में औपचारिकताएं काफी समय से पूरी हो गई हैं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बिक्री से प्राप्त राशि को तुरंत उपरोक्त पते पर मुझे अग्रेषित करें।

(6) 15 नवंबर, 1960 को, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को लिखा कि एस्टेट ऑफिसर के आदेशों के तहत प्रतिवादी से संबंधित भूखंड पूर्व के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया था। अपीलकर्ता को सरकार द्वारा 31 मार्च, 1961 से पहले निर्माण पूरा करने के लिए एक नोटिस दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर सरकार भूखंड को फिर से शुरू करेगी। उन्होंने प्रतिवादी से अनुरोध किया कि वह उन्हें वे पत्र भेजें जो उन्होंने और संपदा अधिकारी ने भूखंड के संबंध में आदान-प्रदान किए थे। वह प्रतिवादी द्वारा किए गए भुगतान का आवंटन पत्र और रसीदें भी चाहते थे और उम्मीद करते थे कि इसे जल्द से जल्द उन्हें भेजा जाएगा। यह पत्र 15 नवंबर, 1960 का है, 29 नवंबर, 1960 के अपने पत्र के *माध्यम से*, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को संबंधित कागजात भेजने का वादा किया और उनसे अनुरोध किया कि वह प्रॉपर्टी डीलरों को बिक्री आय की शेष राशि भेजने के लिए राजी करने में अपने पद का उपयोग करें। इस पर प्रॉपर्टी डीलर्स ने 22 दिसंबर, 1960 के अपने पत्र के साथ प्रतिवादी को 6,828 रुपये का चेक भेजा। भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने पर यह चेक प्रतिवादी को अवैतनिक लौटा दिया गया था। इसके बाद प्रतिवादी ने संपदा अधिकारी, चंडीगढ़ को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि या तो वह भूखंड की कीमत वापस करे या अपीलकर्ता को उसे भेजने का निर्देश दे। प्रतिवादी द्वारा कथित रूप से किए गए आवेदन के परिणामस्वरूप भूखंड को स्थानांतरित कर दिया गया था, संपत्ति अधिकारी स्वाभाविक रूप से 1 अप्रैल, 1961 के अपने पत्र में

प्रतिवादी द्वारा किए गए अनुरोधों में से किसी को भी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था। 15 जून, 1961 को, प्रतिवादी ने सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, आसनसोल की अदालत में धारा 420/417/409 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता (प्रतिवादी नंबर 1 के रूप में वर्णित) और मेसर्स पीएल साहनी एंड कंपनी, प्रॉपर्टी डीलरों (प्रतिवादी नंबर 2 के रूप में वर्णित) के श्री बीएस ढिल्लों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के संबंधित भाग निम्नानुसार हैं:-

"2. आरोपी नंबर 1 ने आरोपी नंबर 2 के साथ मिलकर उपरोक्त भूखंड की बिक्री के लिए शिकायतकर्ता से संपर्क किया और शिकायतकर्ता 7,500 रुपये की कीमत पर जमीन हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो गया और यह भी तय किया गया कि शिकायतकर्ता को 7 रुपये की शुद्ध राशि मिलनी थी। कमीशन प्रभार ोें आदि की कटौती के बाद 32806 रु।

(3) शिकायतकर्ता के मन में विश्वास पैदा करने के लिए, आरोपी नंबर 1 ने आरोपी नंबर 2 के माध्यम से शुरू में 500 रुपये की राशि दी और शिकायतकर्ता से अनुरोध किया कि वह आरोपी नंबर 1 के नाम पर उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण के तथ्य को एस्टेट अधिकारी को लिखित रूप में दें। कैपिटल प्रोजेक्ट, चंडीगढ़ और आरोपी व्यक्तियों ने आश्वासन दिया कि शिकायतकर्ता को निर्धारित राशि की शेष राशि का भुगतान किया जाएगा जैसे ही वह आरोपी व्यक्तियों को इस तरह के हस्तांतरण का समर्थन करते हुए एक हलफनामा भेजेगा।

(4) इस प्रकार इस शिकायतकर्ता को प्रेरित करते हुए आरोपी व्यक्तियों ने इस शिकायतकर्ता द्वारा श्री एस. के. मुखर्जी, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आसनसोल के समक्ष एक हलफनामा दायर किया, जिसमें उनके बयानों पर विश्वास किया गया कि उक्त शपथ पत्र प्राप्त होने पर 6.828 रुपये की राशि का भुगतान तुरंत किया जाएगा।

(8) शिकायतकर्ता ने आरोपी व्यक्तियों को भुगतान न किए जाने के तथ्य से अवगत कराया, लेकिन आरोपी व्यक्ति इस मामले पर चुप हैं और आरोपी व्यक्तियों ने कई मांग पत्रों के बावजूद इस तारीख तक इस शिकायतकर्ता को 6,828 रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया है।

(9) यह कि इस शिकायतकर्ता ने आरोपी व्यक्तियों को शपथ नहीं दिलाई होगी और उक्त हलफनामा नहीं भेजा होगा यदि वह शिकायतकर्ता को धोखा देने के उनके ऐसे बेईमान इरादे को जान सकता है। मुकदमे के समय विस्तृत साक्ष्य पेश किए जाएंगे।

इस शिकायत को आसनसोल के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा जांच और रिपोर्ट के लिए स्थानीय पुलिस को चिह्नित किया गया था। आसनसोल में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत शिकायतकर्ता का बयान उस तरीके को इंगित नहीं करता है जिसमें अपीलकर्ता को किसी भी अपराध से जुड़ा कहा जा सकता है और फिर भी अपीलकर्ता को चंडीगढ़ में गिरफ्तार किया गया और लगभग दो घंटे तक हिरासत में रहने के बाद एक स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया। अपीलकर्ता 6 अप्रैल, 1962 को आसनसोल में विद्वान उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हुआ, और यह कहा गया है कि वह लगभग दो साल तक उस अदालत में उपस्थित रहा, जब उसे इस आधार पर आरोपमुक्त कर दिया गया कि उसके खिलाफ कोई *प्रथम दृष्टया* मामला नहीं बनाया गया था। प्रॉपर्टी डीलर श्री बी. एस. ढिल्लों और प्रॉपर्टी डीलर पी. एल. साहनी के खिलाफ कार्यवाही के परिणामस्वरूप उन्हें बरी कर दिया गया।

(7) अपीलकर्ता ने चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में तत्काल मुकदमा दायर किया। इन आरोपों पर कि उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत स्थापित करने में प्रतिवादी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से और बिना किसी उचित या उचित कारण के काम किया। अपीलकर्ता को इस आपराधिक मामले का बचाव करने के लिए 14,395 रुपये का खर्च उठाना पड़ा। 53 वर्ष की आयु तक पुन: रोजगार के नुकसान के कारण उन्होंने 75,000 रुपये की क्षति का दावा किया और मानसिक चिंताओं और शारीरिक असुविधा और प्रतिष्ठा की हानि के लिए 10,000 रुपये का दावा किया गया। हालांकि, अपीलकर्ता ने अदालत शुल्क बचाने के लिए अपने दावे को घटाकर 25,000 रुपये कर दिया। लिखित बयान में, प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि वह अपीलकर्ता और प्रॉपर्टी डीलरों, मेसर्स पीएल साहनी एंड कंपनी के बीच क्या बातचीत हुई, इस बात से अनजान था, न ही उसे पता था कि अपीलकर्ता ने उन्हें कोई राशि का भुगतान किया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि 16 अगस्त, 1960 को हस्तांतरण का हलफनामा केवल प्रतिवादी की भूखंड को स्थानांतरित करने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन अपने आप में एक दस्तावेज नहीं था जो वास्तव में अपीलकर्ता को भूखंड के हस्तांतरण को अधिकृत करता था। संपदा अधिकारी की पुस्तकों में प्लॉट का वास्तविक हस्तांतरण, यदि कोई हो, गलत और अनधिकृत था। बिक्री राशि के संबंध में प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा भेजे गए चेक का अनादर किया गया था। प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के खिलाफ कोई दुर्भावना या दुर्भावना नहीं रखी। विद्वान सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट पर उनका कोई प्रभाव नहीं था और न ही उन्होंने पुलिस द्वारा जांच के लिए शिकायत को चिह्नित किया था। उन्होंने अपीलकर्ता को गिरफ्तार भी नहीं करवाया। आगे यह आरोप लगाया गया कि मेसर्स पीएल साहनी एंड कंपनी को केवल एक संभावित खरीदार का पता लगाने की सलाह दी गई थी। वे प्लॉट को स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत नहीं थे और अपीलकर्ता प्रतिवादी को कीमत का भुगतान करने के लिए कर्तव्यबद्ध था।

एस्टेट ऑफिस में इस ट्रांसफर को पंजीकृत कराने से पहले वह प्रॉपर्टी डीलरों को कीमत के अपने कथित भुगतान के पीछे शरण नहीं ले सकता था।

(8) पक्षकारों की दलीलों पर, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे: -

(1) क्या मुकदमा समय के भीतर है?

(2) क्या वादपत्र कार्रवाई के किसी कारण का खुलासा नहीं करता है?

(3) क्या वादी पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से और बिना किसी उचित और संभावित कारण के मुकदमा चलाया गया था?

(4) यदि मुद्दा नहीं है। (3) साबित होता है, क्या वादी वाद के पैरा 10, 11 और 12 में दिए गए विवरण के अनुसार क्षतिपूर्ति का हकदार है?

(5) क्या प्रतिवादी किसी भी क्षति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, भले ही अभियोजन दुर्भावनापूर्ण रूप से और बिना किसी उचित या संभावित कारण के किया गया हो, इस तथ्य के कारण कि अभियोजन वास्तव में राज्य द्वारा शुरू किया गया था?

(6) क्या प्रतिवादी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35-ए के तहत विशेष लागत का हकदार है?

(7) अनुतोष

(9) विद्वान ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे को समय के भीतर होने के लिए कहा। मुद्दा सं. (2) प्रतिवादी के खिलाफ फैसला सुनाया गया था। मुद्दा सं 2008 के संबंध में। (3), यह माना गया कि प्रतिवादी ने शिकायत में झूठे आरोप लगाते हुए खुद को अभियोजक के पद पर पहुंचा दिया और इस दलील के पीछे शरण नहीं ले सका कि उसने केवल उन अधिकारियों को सूचित किया जिन्होंने स्वयं मामले की जांच की और अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन शुरू किया। लेकिन प्रतिवादी द्वारा दायर हलफनामे को प्लॉट के वास्तविक हस्तांतरण के विपरीत उसे हस्तांतरित करने के उसके इरादे के रूप में व्याख्या की गई थी। ट्रायल कोर्ट का विचार था कि वास्तविक हस्तांतरण को लागू करने के लिए प्रतिवादी की ओर से दायर आवेदन पर उसके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और इसलिए वह एक उचित दलील पर विचार कर सकता था कि अपीलकर्ता धोखाधड़ी में एक पक्ष था। इस मुद्दे पर अपीलकर्ता के खिलाफ और प्रतिवादी के पक्ष में फैसला किया गया था। हर्जाने की मात्रा के बारे में न्यायालय का विचार था कि अपीलकर्ता ने 26 मार्च, 1965 के अपने बयान के माध्यम से अपने दावे को केवल 25,000 रुपये की सीमा तक सीमित कर दिया और 74,395 रुपये के शेष दावे को छोड़ दिया। इससे, यह अनुमान लगाया गया था कि अपीलकर्ता ने तीन मदों के तहत वास्तव में हुए नुकसान की राशि को आनुपातिक रूप से कम कर दिया था, अर्थात्, आसनसोल में स्थापित आपराधिक मामले में खुद का बचाव करने के लिए उसके द्वारा किए गए खर्च, अपीलकर्ता के पुन: नियोजित होने में विफल रहने के कारण कमाई का नुकसान, और मानसिक चिंताओं के कारण नुकसान। इस तरह, मानसिक चिंताओं और अपने बचाव पर अपीलकर्ता द्वारा किए गए खर्च के कारण नुकसान की राशि की गणना केवल 6,150 रुपये पर की गई थी। नहीं। पुन: रोजगार के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की गई क्योंकि इसे एक अनिश्चित मामला माना जाता था। यह मामला अंक सं 2008 में निहित है। (5) को अंक सं 2009 द्वारा कवर किया गया था। (4) और इस प्रकार इस पर कोई अलग निष्कर्ष नहीं दिया गया था। मुद्दा सं. (6) प्रतिवादी के खिलाफ फैसला किया गया था और इन मुद्दों पर विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता का मुकदमा खारिज कर दिया गया था।

(10) अपील में हमारे समक्ष यह आग्रह किया गया है कि अपीलकर्ता, जिस पर झूठे आरोपों के आधार पर मुकदमा चलाया गया है और प्रथम दृष्टया सबूत न होने के कारण आरोपमुक्त कर दिया गया है, वह कम से कम 6,150 रुपये तक के नुकसान का दावा करने का हकदार है। सालमंड द्वारा लिखित 'द लॉ ऑफ टॉर्ट्स', चौदहवें संस्करण (1965) के पृष्ठ 588 पर, यह निम्नानुसार कहा गया है: -

> "दुर्भावनापूर्ण अभियोजन या अपमानजनक प्रक्रिया के अन्य रूपों के लिए कार्रवाई की जाएगी, जिन्हें संदर्भित किया गया है, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए: –
>
> 1. कार्यवाही प्रतिवादी द्वारा स्थापित या जारी की जानी चाहिए;
> 2. उन्होंने उचित और संभावित कारण के बिना काम किया होगा;
> 3. उसने दुर्भावनासे काम किया होगा;

4. मामलों के कुछ वर्गों में कार्यवाही असफल रही होगी - यानी, अब मुकदमा करने वाले वादी के पक्ष में समाप्त हो जाना चाहिए।

(11) वादी के सफल होने से पहले इन सभी शर्तों को सह-अस्तित्व में होना चाहिए। हमें अब यह देखना है कि क्या अपीलकर्ता उपरोक्त शर्तों को रिकॉर्ड पर साबित करने में सक्षम है या नहीं। इस निर्णय के पिछले भाग में चर्चा किए गए साक्ष्य से, निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं: –

(a) प्रॉपर्टी डीलरों ने प्रतिवादी से प्लॉट की बिक्री करने के लिए कभी नहीं कहा। दूसरी ओर, प्रतिवादी के एक मित्र श्री आर. एन. चोना ने उनसे संपर्क किया, कीमत तय की, अग्रिम राशि के रूप में 500 रुपये का चेक प्राप्त किया और उसे उत्तरदाता को भेज दिया और उसे सीधे प्रॉपर्टी डीलरों से संपर्क करने के लिए कहा।

(b) प्रतिवादी, जैसा कि उनके मित्र श्री चोना ने सुझाव दिया था, ने प्रॉपर्टी डीलरों के साथ पत्राचार किया और कुछ स्पष्टीकरण मांगे। उन्होंने प्लॉट के हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से चंडीगढ़ आने के लिए अपनी अनिच्छा भी दिखाई थी और इच्छा व्यक्त की थी कि प्रॉपर्टी डीलरों को उनसे अधिकार पत्र प्राप्त होने पर उनकी ओर से यह कार्य करना चाहिए।

(c) एक स्तर पर प्रतिवादी ने लेनदेन से पीछे हटने का प्रयास किया, लेकिन उसे प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा ऐसा करने से मना कर दिया गया, जिन्होंने उसे सूचित किया कि इच्छुक खरीदार ने उन्हें भूखंड की पूरी कीमत का भुगतान किया है और सौदा करना उसके अपने हित में होगा।

(d) प्रतिवादी ने प्रॉपर्टी डीलरों के कहने पर उन्हें एक सत्यापित हलफनामा भेजा जिसमें कहा गया था कि वह अपीलकर्ता के पक्ष में भूखंड बेचना चाहता है। उन्होंने एस्टेट ऑफिस को कभी सूचित नहीं किया कि प्लॉट वास्तव में उनके द्वारा बेचा गया था।

(e) एस्टेट अधिकारी को इस आशय का आवेदन कि प्रतिवादी ने प्लॉट बेच दिया था, श्री आहूजा द्वारा किया गया था, जो प्रॉपर्टी डीलरों के कर्मचारी थे और जिन्हें वास्तव में प्रतिवादी द्वारा अपनी ओर से हस्तांतरण करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था।

(f) अपीलकर्ता ने संपदा अधिकारी को दिए अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उसने हस्तांतरण के लिए पूरी राशि का भुगतान किया था। आवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि प्रतिवादी के एजेंट के रूप में प्रॉपर्टी डीलरों को विचार राशि का भुगतान किया गया था।

(g) एस्टेट ऑफिस, चंडीगढ़ ने अपीलकर्ता के पक्ष में भूखंड के हस्तांतरण को प्रभावी किया, जिसने उचित समय पर प्रतिवादी को इस तथ्य से अवगत कराया और उनसे भुगतान रसीदों सहित आवश्यक दस्तावेज भेजने का अनुरोध किया।

(h) इस स्तर पर प्रतिवादी ने स्थानांतरण को एक सिद्ध तथ्य के रूप में माना और अपीलकर्ता के समक्ष कोई विरोध दर्ज नहीं कराया कि प्रॉपर्टी डीलरों के कर्मचारी श्री आहूजा को उनके द्वारा दिए गए किसी भी लिखित अधिकार के अभाव में यह हस्तांतरण उनके पक्ष में कैसे किया गया था। "उसने अपीलकर्ता से केवल अनुरोध किया कि वह प्रॉपर्टी डीलरों के साथ अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करे और उन्हें उसे भेजे; विचार धन।

(j) अपीलकर्ता द्वारा पूछे जाने पर प्रॉपर्टी डीलरों ने प्रतिवादी को 6,828 रुपये का चेक भेजा,

जिसमें उनके कमीशन और प्रतिवादी द्वारा पहले से प्राप्त 500 रुपये की अग्रिम राशि को बिक्री से काट लिया गया।

(k) प्रतिवादी ने अपीलकर्ता और उक्त प्रॉपर्टी डीलरों के साझेदार श्री बीएस ढिल्लों के खिलाफ 15 जून, 1961 को आसनसोल में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट की अदालत में एक आपराधिक शिकायत दायर की, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित कथन किए, जिन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा सही पाया गया था: –

(A) कि इस वादी ने बीएस ढिल्लों के साथ संपत्ति की बिक्री के लिए उनसे संपर्क किया;

(B) कि प्रतिवादी के मन में विश्वास पैदा करने के लिए इस वादी ने बीएस ढिल्लों के माध्यम से उसे 500 रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान किया और वादी ने उससे (प्रतिवादी से) अनुरोध किया कि वह अपने (वादी के) पक्ष में उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण के तथ्य को लिखित रूप में संपदा अधिकारी को दे। चंडीगढ़, और तब इस वादी ने यह आश्वासन भी दिया कि शेष बिक्री मूल्य का भुगतान किया जाएगा जैसे ही प्रतिवादी हस्तांतरण की गणना करते हुए एक हलफनामा भेजता है।

(C) कि इस वादी ने प्रतिवादी को पूर्वोक्त के रूप में ऐसा हलफनामा देने के लिए भी प्रेरित किया।

" ^^*एस।

(D) कि वादी ने सीधे उसे बताया कि हलफनामा प्राप्त होने पर बिक्री मूल्य का भुगतान तुरंत किया जाएगा।

(1) अपीलकर्ता को आपराधिक न्यायालय ने इस आधार पर आरोपमुक्त कर दिया था कि उसके खिलाफ *प्रथम दृष्टया* कोई मामला स्थापित नहीं हुआ था।

(12) इन तथ्यों के आधार पर, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता एक डिक्री का हकदार था। उन्होंने सतदेव *प्रसाद और एक अन्य बनाम राम नारायण और अन्य* (1) *को हमारे ध्यान में लाया* है।, जिसमें यह माना गया है कि जहां वादी के खिलाफ आरोप एक अपराध के संबंध में था, जिसे प्रतिवादी ने उसे करते हुए देखने का दावा किया था, और मुकदमा गुण-दोष के आधार पर बरी होने में समाप्त होता है, तो अनुमान न केवल यह होगा कि वादी निर्दोष था, बल्कि यह भी कि आरोप के लिए कोई उचित और संभावित कारण नहीं था। गोबिंद *चंद्र सांबरसिंह महापात्रा* बनाम *उपेंद्र पाधी और एक अन्य मामले* (2) *पर* इसी तरह के प्रस्ताव के लिए *भरोसा किया गया था* ,

(13) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने हमारे समक्ष आग्रह किया है कि प्रतिवादी ने, एक पीड़ित व्यक्ति होने के नाते, केवल सक्षम न्यायालय के समक्ष तथ्यों को रखकर कानून को गति में लाया था। अदालत ने खुद शिकायत को जांच के लिए पुलिस को भेज दिया। यदि, इस जांच के परिणामस्वरूप, पुलिस ने वास्तव में अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया था और उसे कानून की अदालत के समक्ष परीक्षण के लिए रखा था, तो प्रतिवादी को किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था। संक्षेप में, यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी को अभियोजक के रूप में नहीं माना जा सकता है। हम असमर्थ हैं! प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलील से सहमत हूं। अभियोजन के लिए मुकदमे में एक प्रतिवादी केवल तभी दायित्व से बच सकता है जब वह पुलिस या मजिस्ट्रेट के समक्ष सही और सही जानकारी रखता है, जिसके पास वादी के खिलाफ लगाए गए अपराध का संज्ञान

लेने का अधिकार है। जहां एक प्रतिवादी भौतिक तथ्यों को छुपाता है या उन्हें अनुचित सीमा तक विकृत करता है, उसे यह आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह अभियोजक नहीं था।

(1) ए.आई.आर. 1969 पटना 102.
(2) ए.आई.आर. 1960 उड़ीसा 29.

बलभद्र सिंह और एक अन्य *बनाम <u>बद्री साह और एक अन्य</u>* (3) <u>मामले मे</u>, यह निम्नानुसार देखा गया: –

"किसी भी देश में, जहां भारत की तरह, अभियोजन निजी नहीं है, किसी जन के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन अधिकारियों को जानकारी देना जो स्वाभाविक रूप से अभियोजन की ओर ले जाता है, बस एक ही बात है। और अगर ऐसा किया जाता है और परेशानी के कारण कार्रवाई होती है तो झूठ होगा। लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि, जहां तक पुलिस का संबंध है, अभियोजन की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त कारण थे।

(3) ए. आई.आर. 1926 पी.सी. 46.

(14) यह पहले ही देखा जा चुका है कि कुछ सामग्री बिंदुओं पर प्रतिवादी ने शिकायत में जानबूझकर झूठे बयान दिए थे। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी को अभियोजक के रूप में नहीं माना जा सकता है। यदि उसके दायित्व की अन्य शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो वह केवल इसलिए अपनी कार्रवाई के परिणामों से बच नहीं सकता क्योंकि मजिस्ट्रेट या पुलिस की एजेंसी ने भी हस्तक्षेप किया था।

(15) अब यह देखना होगा कि क्या प्रतिवादी ने शिकायत दर्ज करते समय उचित और संभावित कारण के बिना काम किया या नहीं। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले पर विचार किया और कहा कि प्रतिवादी द्वारा शपथ लिए गए हलफनामे में यह नहीं कहा गया है कि संपत्ति अपीलकर्ता के पक्ष में स्थानांतरित कर दी गई थी। यह केवल यह दर्शाता है कि प्रतिवादी विवाद में प्लॉट को स्थानांतरित करना चाहता था। यह हलफनामा अकेले हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया था और इस कारण से प्रतिवादी की ओर से दायर किया गया आवेदन यह दिखाने के लिए जाली था कि संपत्ति वास्तव में हस्तांतरित की गई थी। अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि अपीलकर्ता ने अपने स्वयं के गवाह के रूप में पेश होते हुए क्रॉस-एग्जामिनेशन में कहा कि उसने 27 अगस्त, 1960 को एस्टेट ऑफिसर को विवादित भूखंड को अपने पक्ष में स्थानांतरित करने के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था। इन परिस्थितियों पर विचार करने पर, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विवादित भूखंड का हस्तांतरण अपीलकर्ता के पक्ष में फर्जी तरीके से किया गया था और "यह, मेरी राय में, प्रतिवादी को इस आरोप से मुक्त करता है कि उसके पास इस संबंध में वादी के खिलाफ कोई उचित और संभावित कारण नहीं था।

अपीलकर्ता के वकील ने हालांकि, इस बिंदु पर चुनौती दी है। उनके अनुसार, प्रतिवादी ने खुद चंडीगढ़ आने के लिए अपनी अनिच्छा दिखाई और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत ों से यह स्थापित होता है कि प्रतिवादी ने प्रॉपर्टी डीलरों को अपनी ओर से विचार राशि स्वीकार करने और बिक्री

पूरी होने के बाद उसे भेजने के लिए अधिकृत किया था। बिक्री होने के बाद , अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को इस मामले के बारे में सूचित किया, लेकिन प्रतिवादी ने कभी विरोध नहीं किया कि विवादित भूखंड अपीलकर्ता के पक्ष में कैसे स्थानांतरित किया गया। विवाद केवल है! पैसे के भुगतान या गैर-भुगतान से संबंधित और कोई भी उचित व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी पर कोई धोखाधड़ी की थी। तथापि, हमारा विचार है कि इस बिंदु पर विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निष्कर्ष वास्तव में अकाट्य हैं। दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के मुकदमे में, यह साबित करने का बोझ कि कार्यवाही बिना किसी उचित और संभावित कारण के शुरू की गई थी) वादी पर है जो नुकसान की मांग करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले की कार्यवाही में वादी के बरी होने से कभी-कभी एक धारणा को जन्म मिल सकता है कि उसके अभियोजन के लिए कोई उचित और संभावित कारण नहीं था, लेकिन यह धारणा खंडन योग्य है। इस तरह के मुकदमे में प्रतिवादी को केवल यह साबित करना है कि तथ्य और परिस्थितियां मौजूद थीं जिसने उसके मन में एक विश्वास को जन्म दिया कि दूसरा पक्ष दोषी था। इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखने या तौलने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि कानून की अदालत द्वारा किया जाएगा, अन्यथा उन सभी मामलों में जिनमें अभियोजन विफल हो जाता है, शिकायतकर्ता या अभियोजक नुकसान के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। सर जॉन सैलमंड द्वारा उल्लिखित सभी चार शर्तों को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के मुकदमे में प्रतिवादी को दायित्व के बोझ से बोझिल होने से पहले सह-अस्तित्व में होना चाहिए। फिर, ऐसे लेनदेन के मामले में जिसमें धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाता है, धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति देर से चरण तक मामले की कुछ परिचारक परिस्थितियों से अनभिज्ञ रहता है। यदि कोई व्यक्ति भविष्य में क्या होने वाला है, इसकी कल्पना या पूर्वानुमान कर सकता है, तो वह कभी भी धोखाधड़ी का शिकार नहीं होगा।

वर्तमान मामले में इन परीक्षणों को लागू करते हुए, हम पाते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर प्रतिवादी को प्रतिनिधित्व कर रहे थे कि विवादित भूखंड की कीमत हस्तांतरण के पूरा होने के बाद उसे भुगतान की जाएगी। प्रतिवादी, हालांकि प्लॉट के हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए चंडीगढ़ की यात्रा से बचना चाहता था, उसने अभी तक प्रॉपर्टी डीलरों को सूचित किया था कि उससे अधिकार प्राप्त करने के बाद हस्तांतरण किया जाना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने इस धारणा को स्वीकार किया हो कि उन्हें एक विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी भेजने के लिए बुलाया जाएगा। जाहिर है, इस आसानी से कोई लिखित प्राधिकरण न तो प्रॉपर्टी डीलरों या उनके कर्मचारी श्री आहूजा के पक्ष में भेजा गया था। प्रतिवादी इस धारणा में रहा कि पैसा उसे भेज दिया जाएगा। जब चेक बाउंस हो गया, तब जाकर उन्हें उस स्थिति का एहसास हुआ, जिसमें वह खुद उतरे थे। बाद में, जब बाद के तथ्य उनकी जानकारी में आए, तो उन्होंने पाया कि प्लॉट के वास्तविक हस्तांतरण के लिए आवेदन पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे उन्होंने ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं किया था। अपीलकर्ता की ओर से दायर आवेदन से यह भी पता चला कि उसने एस्टेट ऑफिसर के समक्ष आग्रह किया था कि प्रतिवादी को पूरी राशि का भुगतान किया गया था। यह बयान तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि प्लॉट की कीमत प्रॉपर्टी डीलरों को दी गई थी। इन सभी परिस्थितियों को एक साथ लेने पर उसे विश्वास हो सकता था कि उसे न केवल प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा धोखा दिया गया था, बल्कि अपीलकर्ता का भी इस मामले में हाथ था। उचित और संभावित कारण की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर विचार करते समय एक न्यायालय को परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करना होगा। केवल इसलिए कि अभियोजक ने यहां और वहां जानबूझकर झूठ पेश किया था, यह साबित करने के लिए नहीं लिया जा सकता है कि संभावित कारण पूरी तरह से अनुपस्थित था। *बलभद्दर सिंह के मामले* (3) (उपर्युक्त) *में,* प्रिवी काउंसिल ने निम्नानुसार टिप्पणी की: –

"सवाल यह नहीं है, 'क्या वादी ने अपराध किया' या प्रतिवादी ने वादी के खिलाफ अपराध का आविष्कार किया, दो प्रश्न स्थिति की संभावनाओं को समाप्त करते हैं। सवाल यह है कि क्या वादी ने साबित कर दिया है कि प्रतिवादी ने अभियोजन के लिए पूरी कार्यवाही का आविष्कार किया और उकसाया।

इस परिच्छेद में 'संपूर्ण कार्यवाही' वाक्यांश का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायालय को मामले के मूल तक पहुंचना होगा और यह देखना होगा कि अपराध का उप-स्तर मौजूद है या नहीं। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण परिस्थितियां थीं: सबसे पहले, संपत्ति को एक आवेदन के आधार पर अपीलकर्ता के पक्ष में स्थानांतरित किया गया था, जिस पर न तो प्रतिवादी द्वारा और न ही उसके विधिवत नियुक्त वकील द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, और दूसरी बात यह है कि अपीलकर्ता ने एस्टेट ऑफिसर को प्रतिनिधित्व किया था कि प्रतिवादी को विचार राशि का भुगतान किया गया था। अपीलकर्ता इस तथ्य से भी बहुत कम लाभ प्राप्त कर सकता है कि जब उसने प्रतिवादी को अपने पक्ष में भूखंड के हस्तांतरण के पूरा होने के बारे में सूचित किया, तो प्रतिवादी ने कभी कोई विरोध नहीं किया। प्रतिवादी उस समय आसनसोल में रह रहा था और संभवत: उसे अन्य दस्तावेजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था जो भूखंड के हस्तांतरण के लिए उसके द्वारा भेजे गए हलफनामे के साथ एस्टेट अधिकारी के समक्ष दायर किए गए थे। उचित और संभावित कारण के अस्तित्व को उस समय उसकी मनःस्थिति के संबंध में आंका जाना चाहिए जब उसने कार्यवाही शुरू की थी।

(16) मामले को देखने का एक और तरीका है। जहां तक उक्त प्रॉपर्टी डीलरों की फर्म के भागीदार श्री बी. एस. ढिल्लों का संबंध है, इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि प्रतिवादी को उनके द्वारा धोखा दिया गया था। उन्हें शुरू से ही यह समझने के लिए दिया जा रहा था कि ट्रांसफर की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद प्लॉट की कीमत उन्हें भेज दी जाएगी। इस अभ्यावेदन पर कार्रवाई करते हुए, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता का एक हलफनामा भेजा। प्रतिवादी ने उक्त प्रॉपर्टी डीलरों को लिखा था कि उससे अधिकार प्राप्त करने के बाद उसकी ओर से भूखंड हस्तांतरित किया जाना चाहिए। एस्टेट ऑफिस में ट्रांसफर दर्ज होने के तुरंत बाद प्लॉट की कीमत प्रतिवादी को नहीं भेजी गई। प्रतिवादी को भेजे जाने पर विचार राशि के संबंध में चेक को प्रॉपर्टी डीलरों के बैंकरों द्वारा सम्मानित नहीं किया गया था। यह कुछ हद तक दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह राशि आज तक प्रतिवादी को अवैतनिक रहती है। इन परिस्थितियों में, श्री बीएस ढिल्लों के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत पूरी तरह से उचित थी। प्रश्न यह है कि क्या उन्हें अपीलकर्ता को श्री ढिल्लों के साथ सह-अभियुक्त के रूप में उल्लेख करना चाहिए था या नहीं। अपीलकर्ता द्वारा संपदा अधिकारी को लिखे गए आवेदन की उपस्थिति में, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को भूखंड की कीमत का भुगतान किया था और कथित रूप से आवेदन श्री आहूजा द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिवादी की ओर से दायर किया गया था, जिनके पास प्रतिवादी की ओर से हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं था, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी वैध रूप से इस विश्वास को स्वीकार नहीं कर सका कि अपीलकर्ता और प्रॉपर्टी डीलरों ने उसे भूखंड से वंचित करने के लिए एक साथ हाथ मिलाया था। रिकॉर्ड पर सबूत हैं कि प्रतिवादी ने यह शिकायत दर्ज करने से पहले कानूनी सलाह ली थी। पुलिस ने शिकायत की जांच की। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं लाया गया है कि प्रतिवादी ने पुलिस को अपीलकर्ता की अवैध गिरफ्तारी करने के लिए प्रेरित किया। उचित और संभावित कारण की अनुपस्थिति को साबित करने का बोझ अपीलकर्ता पर था और यदि वह किसी विशेष बिंदु पर सबूत का नेतृत्व नहीं करता है, तो उसके पक्ष में कोई अनुमान नहीं लगाया जा

सकता है।

(17) विद्वान वकील द्वारा दिया गया अगला तर्क कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक शिकायत करने के लिए सिविल कार्रवाई का गठन करने वाले तथ्यों का उपयोग किया था, भी बिना किसी आधार के है। *राम नाथ* बनाम *बशीर-उद-दीन* (4) में, यह अभिनिर्धारित किया कि यदि प्रतिवादी के पास आपराधिक कानून को गति देने के लिए एक उचित और संभावित कारण है, तो केवल यह तथ्य कि उसने एक नागरिक उपचार का पालन किया होगा, उसे दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं बना सकता है।

(18) यह परिस्थिति कि कार्यवाही चंडीगढ़ में शुरू होने के बजाय आसनसोल में शुरू की गई थी, अपीलकर्ता की मदद नहीं करती है। यह पार्टियों का स्वीकार किया गया मामला है कि प्लॉट की बिक्री के बारे में बातचीत प्रतिवादी के साथ की गई थी, जब वह आसनसोल में तैनात था। बिक्री मूल्य के संबंध में चेक भी उन्हें भेजा गया था और आसनसोल में बाउंस कर दिया गया था। *के. सतवंत सिंह* बनाम *पंजाब राज्य* (5) में कहा गया था कि "जबकि आरोपी द्वारा गलत बयानी शिमला में थी और परिणाम लाहौर में था क्योंकि बर्मा सरकार लाहौर में संपत्ति देने के लिए गलत बयानी से प्रेरित थी, आरोपी द्वारा धोखाधड़ी के अपराध पर लाहौर या शिमला में मुकदमा चलाया जा सकता था। नारायण दास बनाम *प्रेम चंद* (6) में, 'A' को 'B' के लिए एक निश्चित धनराशि देनी थी। उन्होंने गुजरात जिले के एक स्थान को संबोधित डाकघर के माध्यम से 'बी' को 400 रुपये का बीमित पत्र भेजा, जिसमें ऋण के निर्वहन के प्रमाण के रूप में 'बी' द्वारा डाकघर को दी गई रसीद का उपयोग करने का इरादा था। 'ए' ने गुजरात में एक मजिस्ट्रेट की अदालत में 'बी' के खिलाफ शिकायत दर्ज की। कोल्डस्ट्रीम जे ने कहा कि गुजरात की अदालत के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 177 और 179 के तहत अपराध की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है। इसी तरह का कानून लाहौर में पंजाब के मुख्य न्यायालय द्वारा ईशर दास बनाम *सम्राट* (7) मामले *में भी निर्धारित किया गया था।*, जो लाहौर में मुख्य न्यायालय का पूर्ण न्यायालय का निर्णय है। यदि प्रतिवादी के पास आपराधिक शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार क्षेत्र था, तो यह केवल इसलिए गायब नहीं हो जाता है क्योंकि शिकायत आसनसोल में दर्ज की गई थी। जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है कि अधिकारियों का वजन आसनसोल में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के पक्ष में है।

(19) पूरे मामले पर समग्र विचार करने पर, हम यह विचार करने के इच्छुक हैं कि अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी के पास अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए कोई उचित और संभावित कारण नहीं था।

(4) ए.आई.आर. 1953 पंजाब 213.
(5) ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 266.
(6) 132 (1931) आई.सी. 864.
(7) 8 (1908) सी आर.एल.जे. 75.

(20) अब दुर्भावना के सवाल पर आते हुए, यह शुरू में कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी ने उसके खिलाफ कोई दुर्भावना या दुश्मनी रखी थी। हालांकि, अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि आसनसोल में उनके

मुवक्किल के खिलाफ शिकायत उन्हें परेशान करने और उन्हें दो बार पैसे का भुगतान करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से दर्ज की गई थी। यदि आसनसोल की अदालत के पास शिकायत पर विचार करने का अधिकार था, तो प्रतिवादी के खिलाफ दुर्भावना का अनुमान केवल इसलिए नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि उसने उस अदालत से संपर्क किया था, न ही इस परिस्थिति से दुर्भावना का अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के गवाहों से वादा किया था कि अगर उसे प्लॉट की कीमत का भुगतान किया जाता है तो वह उसके खिलाफ मुकदमा वापस ले लेगा। एक व्यक्ति जिसे धोखा दिया जाता है, उसके पास टीडब्ल्यूक्यूआई उपचार उपलब्ध हैं। पहला धन की वापसी के लिए नागरिक कार्रवाई है और दूसरा दोषी व्यक्ति को दंडित करने के लिए आपराधिक अभियोजन है। यदि शिकायतकर्ता आपराधिक अभियोजन के दौरान अपने बकाये की मांग करता है, तो वह केवल कुछ मांग रहा है जिसका वह हकदार है। इस तरह की मांग से किसी बेईमान मकसद का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। एस. टी साहिब बनाम एन हसन गनी साहिब और अन्य (8) में यह निम्नानुसार माना गया: –

"दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए मुकदमे में दुर्भावना अंतिम घटक है। वादी द्वारा मुकदमा चलाने में प्रतिवादी को दुर्भावना से काम करना था, यह भी वादी द्वारा साबित किया जाना है। दुर्भावना का अर्थ है किसी अनुचित और गलत उद्देश्य की उपस्थिति, अर्थात्, कानूनी प्रक्रिया को उसके कानूनी रूप से नियुक्त और उचित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने का इरादा है। इसका अर्थ है सार्वजनिक न्याय या निजी अधिकार को सही ठहराने की इच्छा के अलावा एक अनुचित या अप्रत्यक्ष उद्देश्य। यह जरूरी नहीं कि शत्रुता, बावजूद या दुर्भावना की भावना हो; यह संपार्श्विक लाभ प्राप्त करने की इच्छा के कारण हो सकता है। दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए मुकदमे में स्थापित की जाने वाली दुर्भावना कानून में दुर्भावना भी नहीं है, जैसा कि जानबूझकर गलत कार्य करने से माना जा सकता है, लेकिन वास्तव में दुर्भावना - *मालुस एनिमस* - यह दर्शाता है कि पार्टी को किसी व्यक्ति के प्रति या तो दुर्भावना से, या अप्रत्यक्ष या अनुचित उद्देश्यों से प्रेरित किया गया था। हालांकि ये किसी के प्रति किसी भी प्रतिकूल भावना से पूरी तरह से असंबद्ध हो सकते हैं।

(8) ए.आई.आर. 1957 मद्रास 646.

अभियोजन केवल इसलिए दुर्भावनापूर्ण नहीं है क्योंकि यह क्रोध से प्रेरित है। अभियोजक चाहे कितना भी गलत क्यों न हो, अगर वह ईमानदारी से सोचता है कि आरोपी आपराधिक अपराध का दोषी है तो वह दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का आरंभकर्ता नहीं हो सकता है।

(21) उचित और संभावित कारण की अनुपस्थिति कभी-कभी अदालत को दुर्भावना का निष्कर्ष निकालने का अधिकार दे सकती है, लेकिन जहां अभियोजन पक्ष को उचित विश्वास पर आधारित पाया जाता है, अभियोजक के खिलाफ दुर्भावना का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। संक्षेप में, इस मामले की परिस्थितियों से पता चलता है कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करते समय किसी भी दुर्भावना से प्रेरित नहीं किया था।

(22) पूर्वगामी चर्चा के परिणामस्वरूप, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी के पास अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए कोई उचित और संभावित कारण नहीं था, न ही वह यह स्थापित करने में सक्षम है कि ऐसा करने में प्रतिवादी दुर्भावना से प्रेरित था। इसलिए, यह अपील विफल हो जाती है और लागत के रूप

मेजर ज्ञान सिंह *बनाम* श्री एस पी बत्रा (*शर्मा, न्यायमूर्ति*)

में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है।

संधावलिया, न्यायमूर्ति -मैं सहमत हूं।

बी.एस.जी.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

खुश करण जोत सिंह गिल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी